



Research Article

बस्ती मंडल में नगरीकरण का शैक्षिक सुविधाओं पर प्रभाव

Ganesh Tripathi^{1*}, Prof. Rekha Tiwari²

¹Research Scholar, Dept. of Geography, Buddha P.G. College, Kushinagar, Affiliated from: D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India

²Professor, Dept. of Geography, Buddha P.G. College, Kushinagar, Affiliated with: D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author: Ganesh Tripathi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16933379>

सारांश

यह तहसीलवार विश्लेषण दर्शाता है कि बस्ती जनपद में नगरीकरण के लाभ मुख्यतः बस्ती तहसील में केंद्रित हैं, जबकि रुधौली, भानपुर और हरैया के कुछ हिस्से पीछे हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए जनसांख्यिकीय आँकड़ों, भौगोलिक मानचित्रण और लक्षित नीतिगत प्रयासों का समन्वय आवश्यक है, जिससे सभी तहसीलों में समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित हो सकें।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 21-07-2025
- Accepted: 15-08-2025
- Published: 22-08-2025
- IJCRM:4(4); 2025: 586-595
- ©2025, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

Tripathi G, Tiwari R. बस्ती मंडल में नगरीकरण का शैक्षिक सुविधाओं पर प्रभाव. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(4):586-595.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

कुंजी शब्द: शहरीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, सतत विकास, वैश्वीकरण, आर्थिक वृद्धि

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के समग्र विकास की मूल आधारशिला होती है। एक उन्नत शैक्षिक प्रणाली न केवल आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करती है, बल्कि व्यक्ति की चेतना और जागरूकता को भी जागृत करती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है, वहीं यह प्रक्रिया ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक संसाधनों के वितरण, गुणवत्ता और पहुँच को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। उत्तर प्रदेश का बस्ती मंडल, जो एक बहुभाषी, सांस्कृतिक और भू-आर्थिक रूप से विविध क्षेत्र है, इस संदर्भ में एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र प्रदान करता है। यह शोधपत्र बस्ती मंडल में नगरीकरण की प्रवृत्ति और उससे उत्पन्न प्रभावों का शैक्षिक सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में गहन मूल्यांकन करता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित बस्ती मंडल एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें 12 तहसीलें — हरैया, भानपुर, रूधौली, बस्ती सदर, इटवा, डुमरियागंज, शोहरतगढ़, नौगढ़, बांसी, खलीलाबाद, धनघटा और मेहदावल — शामिल हैं। इन तहसीलों में नगरीकरण का स्तर भिन्न-भिन्न है। कुछ तहसीलें तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही हैं और बेहतर शैक्षिक ढांचा विकसित कर रही हैं, जबकि कुछ अभी भी मुख्यतः ग्रामीण हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच रखती हैं। यह लेख प्रत्येक तहसील के नगरीकरण के स्तर और उसके शैक्षिक अवसरों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है।

1. बस्ती मंडल की सामान्य जानकारी

बस्ती मंडल उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है। यह मंडल तीन जिलों — बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर — से मिलकर बना है और इसमें कुल 12 तहसीलें शामिल हैं। उत्तर में नेपाल सीमा होने के कारण यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मंडल का भौगोलिक विस्तार तराई एवं समतल क्षेत्र में है, जहाँ प्रमुख नदियाँ घाघरा और राप्ती हैं, जो इस क्षेत्र की कृषि को समृद्ध बनाती हैं। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ प्रकार की है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 67,38,944 है, जिसमें 93.65% ग्रामीण और 6.35% शहरी आबादी है। औसत साक्षरता दर 65.39% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। पुरुष साक्षरता दर 75.71% तथा महिला साक्षरता दर 52.81% है।

2. बस्ती मंडल में नगरीकरण का स्तर और विश्लेषण

बस्ती मंडल में नगरीकरण की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से धीमी रही है, किंतु पिछले दो दशकों में इसमें तेज़ी आई है। मंडल की कुछ तहसीलें जैसे बस्ती सदर, नौगढ़ और खलीलाबाद अपेक्षाकृत अधिक शहरीकृत हैं, जहाँ विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, डिजिटल अवसंरचना और प्रशिक्षित शिक्षक अधिक हैं।

मध्यम नगरीकरण वाली तहसीलें जैसे हरैया, इटवा, डुमरियागंज, शोहरतगढ़, बांसी और मेहदावल में कस्बाई क्षेत्रों में सुविधाएँ मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीण हिस्से पिछड़े हुए हैं। कम नगरीकरण वाली तहसीलें भानपुर, रूधौली और धनघटा हैं, जहाँ उच्च शिक्षा संस्थान और

डिजिटल सुविधाएँ नगण्य हैं। यह विभाजन शहरी-ग्रामीण शिक्षा में असमानता को दर्शाता है।

3. बस्ती मंडल में शिक्षा संबंधी डेटा और विश्लेषण

शिक्षा के क्षेत्र में नगरीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या, संसाधनों की गुणवत्ता, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और डिजिटल शिक्षा तक पहुँच अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षक अनुपस्थिति, और डिजिटल साधनों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएँ हैं।

तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, बस्ती सदर में कक्षा 1-5 के 15,422 छात्र और 3,284 शिक्षक हैं, जबकि रूधौली में 13,420 छात्र और केवल 2,015 शिक्षक हैं। यह छात्र-शिक्षक अनुपात में बड़े अंतर को दर्शाता है। इसी प्रकार, डिजिटल सुविधाएँ भी असमान रूप से वितरित हैं — बस्ती सदर, नौगढ़ और खलीलाबाद में स्मार्ट कक्षाएँ और इंटरनेट उपलब्ध है, जबकि भानपुर और रूधौली में इनकी कमी है। शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर अधिक है, जिसका कारण सुरक्षित परिवहन, छात्रावास सुविधाएँ, और समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन असुरक्षा, अलग विद्यालयों की कमी, और सामाजिक बाधाएँ लड़कियों की शिक्षा में रुकावट पैदा करती हैं।

1. हरैया

हरैया क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। यहाँ नगरीकरण मध्यम स्तर का है, जो मुख्यतः बाज़ार कस्बों और प्रशासनिक केंद्रों तक सीमित है।

शैक्षिक प्रभाव: शहरीकरण से कुछ इंटर कॉलेज और कोचिंग सेंटर स्थापित हुए हैं। फिर भी कई गाँव उच्च माध्यमिक विद्यालयों से दूर हैं। डिजिटल शिक्षा सुविधाएँ सीमित हैं और सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी बनी रहती है। शहरी जेबों में प्रशिक्षित शिक्षक और ICT उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

2. भानपुर

भानपुर मुख्यतः ग्रामीण है, जहाँ बिखरी हुई बस्तियाँ और सीमित औद्योगिक/व्यावसायिक विकास है।

शैक्षिक प्रभाव: नगरीकरण बहुत कम है, जिसके कारण उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच कमजोर है। प्राथमिक विद्यालय अधिकांश गाँवों में हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अवसर कुछ कस्बों तक सीमित हैं। निजी निवेश की कमी के कारण छात्र सरकारी संस्थानों पर निर्भर हैं, जो अक्सर संसाधनों की कमी से जूझते हैं। लड़कियों की शिक्षा लंबी दूरी और परिवहन की असुविधा से बाधित होती है।

3. रूधौली

रूधौली में बाज़ार क्षेत्रों के आसपास धीरे-धीरे शहरीकरण हो रहा है, लेकिन अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है।

शैक्षिक प्रभाव: शहरीकरण से मुख्य कस्बे में कुछ निजी विद्यालय खुले हैं, जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन आंतरिक गाँवों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी और ऊँचे छात्र-शिक्षक अनुपात की

समस्या है। डिजिटल विभाजन स्पष्ट है और ई-लर्निंग पहल अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों तक नहीं पहुँची है।

4. बस्ती सदर

बस्ती सदर, जिले का मुख्यालय होने के कारण, मंडल की सबसे अधिक शहरीकृत तहसील है।

शैक्षिक प्रभाव: यहाँ विद्यालय, विश्वविद्यालय, पेशेवर कॉलेज, तकनीकी संस्थान और कोचिंग सेंटर की उच्च सांद्रता है। विज्ञान प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और इंटरनेट-सक्षम कक्षाएँ आम हैं। शिक्षक उपलब्धता अधिक है और महिला शिक्षा का स्तर बेहतर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के कारण शहरी विद्यालयों में भीड़ बढ़ रही है।

5. इटवा

सिद्धार्थनगर जिले की इटवा तहसील में मध्यम स्तर का नगरीकरण है, जो कुछ बाज़ार कस्बों के आसपास केंद्रित है।

शैक्षिक प्रभाव: यहाँ मुख्य कस्बे में छोटे निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान खुले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। ICT आधारित शिक्षा मौजूद है, लेकिन चुनिंदा विद्यालयों तक सीमित है।

6. डुमरियागंज

डुमरियागंज अर्ध-शहरी क्षेत्र है और नेपाल सीमा के नज़दीक होने से व्यावसायिक गतिविधि अधिक है।

शैक्षिक प्रभाव: शहरीकरण ने निजी विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दिया है। शहरी सरकारी विद्यालयों में बेहतर अवसंरचना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय पिछड़े हैं। सीमा-पार व्यापार ने कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारी है, जिससे वे बच्चों को निजी विद्यालय भेज पा रहे हैं।

7. शोहरतगढ़

नेपाल सीमा के पास स्थित शोहरतगढ़ में व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं के कारण मध्यम स्तर का नगरीकरण है।

शैक्षिक प्रभाव: कस्बे में माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता बेहतर है, लेकिन गाँवों में उच्च माध्यमिक संस्थान नहीं हैं। छात्र अक्सर मुख्य कस्बे या सीमा पार पढ़ने जाते हैं। लड़कियों की शिक्षा परिवहन असुरक्षा और सामाजिक बाधाओं के कारण प्रभावित होती है।

8. नौगढ़

सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नौगढ़, बस्ती सदर और खलीलाबाद के बाद सबसे अधिक शहरीकृत है।

शैक्षिक प्रभाव: यहाँ विद्यालय, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में निवेश अधिक है। कंप्यूटर लैब, डिजिटल कक्षाएँ और पुस्तकालय आम हैं। फिर भी ग्रामीण बाहरी इलाकों में गुणवत्ता का अंतर साफ दिखाई देता है।

9. बांसी

बांसी मध्यम आकार का शहरी केंद्र है, जहाँ ऐतिहासिक और व्यावसायिक महत्त्व है।

शैक्षिक प्रभाव: शहरीकरण से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार हुआ है। यहाँ कुछ व्यावसायिक और तकनीकी संस्थान भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक विद्यालयों में अवसंरचना और डिजिटल सुविधाओं की कमी है।

10. खलीलाबाद

संत कबीर नगर जिले का खलीलाबाद तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, जहाँ उद्योग और व्यापार बढ़ रहे हैं।

शैक्षिक प्रभाव: निजी CBSE/ICSE विद्यालय, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा संस्थान तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। शहरी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्धता और डिजिटल निगरानी बेहतर है। लेकिन ग्रामीण पलायन से शहरी विद्यालयों पर दबाव बढ़ा है।

11. धनघटा

धनघटा मुख्यतः ग्रामीण है और केवल छोटे बाज़ार केंद्रों में शहरी विकास दिखता है।

शैक्षिक प्रभाव: धीमे शहरीकरण के कारण शैक्षिक सुविधाओं में सुधार सीमित है। बाज़ार क्षेत्रों के विद्यालयों में थोड़ा बेहतर ढांचा है, लेकिन ग्रामीण विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक, ICT साधन और विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी है।

12. मेहदावल

मेहदावल अर्ध-शहरी है, जहाँ कुछ वाणिज्यिक और लघु उद्योग विकसित हो रहे हैं।

शैक्षिक प्रभाव: कस्बे में निजी विद्यालय और कोचिंग सेंटर बढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालय ही हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थान दूर हैं, और डिजिटल साक्षरता पहल अभी प्रारंभिक अवस्था में है।

तुलनात्मक विश्लेषण

उच्च नगरीकरण एवं बेहतर शिक्षा

- बस्ती सदर, नौगढ़, खलीलाबाद
- संस्थानों की अधिकता, बेहतर अवसंरचना, डिजिटल कक्षाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक।

मध्यम नगरीकरण एवं मिश्रित परिणाम

- हरैया, इटवा, डुमरियागंज, शोहरतगढ़, बांसी, मेहदावल
- कस्बों में सुविधाएँ ठीक, लेकिन गाँवों में पिछड़ापन।

कम नगरीकरण एवं कमजोर शिक्षा अवसंरचना:

- भानपुर, रूधौली, धनघटा
- उच्च शिक्षा की कमी, अवसंरचना का अभाव, डिजिटल पहुँच सीमित।

नीतिगत सुझाव

संसाधनों का समान वितरण: e-MANCHITRA जैसे GIS आधारित योजनाओं से कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान कर नए विद्यालय स्थापित करना।

1. **डिजिटल समावेशन:** ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट और ICT उपकरण उपलब्ध करना।
2. **शिक्षक संतुलन:** योग्य शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने हेतु प्रोत्साहन देना।
3. **महिला शिक्षा प्रोत्साहन:** सुरक्षित परिवहन और छात्रावास सुविधाएँ।
4. **कौशल विकास:** अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।

2. बस्ती मंडल की भौगोलिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

बस्ती मंडल उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक इकाई है, जिसकी भौगोलिक सीमा उत्तर में नेपाल जैसे अंतरराष्ट्रीय देश से मिलती है। यह मंडल रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सीमावर्ती क्षेत्र है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत विविधतापूर्ण भी है (अबूबकर *et al.*, 2021)। बस्ती मंडल में तीन प्रमुख जिले शामिल हैं – बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। प्रत्येक जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक पहचान और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है।

भौगोलिक अवस्थिति और प्राकृतिक संरचना

बस्ती मंडल की भौगोलिक अवस्थिति 26°23' से 27°30' उत्तरी अक्षांश और 82°17' से 83°30' पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह मंडल उत्तर प्रदेश के अन्य मण्डलों — गोरखपुर (पूर्व), अयोध्या (दक्षिण) और देवीपाटन (पश्चिम) से घिरा हुआ है (अदामू *et al.*, 2021)। उत्तर दिशा में इसकी सीमा नेपाल से लगती है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय महत्व प्राप्त करता है। यह मंडल मुख्यतः गंगा के दो प्रमुख सहायक नदियों — घाघरा (सरयू) और राप्ती के मध्य फैला हुआ है। इन दोनों नदियों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र की मिट्टी को उपजाऊ बनाया है, जिससे यहां की कृषि प्रणाली समृद्ध और सघन रही है।

इस मंडल की भौगोलिक संरचना समतल एवं तराई क्षेत्रीय है, जिसमें जलभराव और बाढ़ की प्रवृत्तियाँ मौसमी रूप से देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, विशेषकर धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना और दलहन की फसलों के लिए यह अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। क्षेत्रीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जहाँ गर्मियों में तापमान 35°C तक पहुँचता है और सर्दियों में 5°C तक गिर जाता है। वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण-पश्चिमी मानसून है, जो जून से सितंबर के बीच इस क्षेत्र में औसतन 800-1000 मिमी वर्षा लाता है। इस जलवायु ने इस क्षेत्र में जल संसाधनों और सिंचाई के साधनों की विविधता सुनिश्चित की है, विशेषकर नहरें, तालाब और ट्यूबवेल के रूप में।

प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि संभावनाएं

बस्ती मंडल की जलवायु और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इसे एक कृषि-प्रधान क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है। यहाँ की मिट्टी की संरचना में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil) पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। बस्ती मंडल में तीन प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से देखी जाती है – नदियों के किनारे की नई जलोढ़ मिट्टी (खादर), पुरानी जलोढ़ मिट्टी (बांगर) और बलुई दोमट

मिट्टी। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में दलदली मिट्टी (तराई) और पथरीली मिट्टी भी देखने को मिलती है।

प्राकृतिक संसाधनों में जल, मिट्टी और वनस्पति के अतिरिक्त जीव-जंतुओं की विविधता भी शामिल है। यहाँ के तराई क्षेत्रों में पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ, मत्स्य संसाधन और उभयचर प्राणी पाए जाते हैं (हम्बल *et al.*, 2021)। बस्ती मंडल की प्रमुख नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों में मत्स्य पालन भी एक महत्वपूर्ण आजीविका स्रोत है।

प्रशासनिक ढाँचा और विकासात्मक विभाजन

बस्ती मंडल में 3 जिले, 12 तहसीलें, 37 विकास खंड, 2094 ग्राम पंचायतें, 4 नगर पालिका परिषदें और 13 नगर पंचायतें हैं। यह प्रशासकीय संरचना यह स्पष्ट करती है कि यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण संरचना वाला है। यहाँ की ग्रामीण और शहरी विकास नीतियाँ इस संरचना के आधार पर बनाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर योजनाओं का संचालन होता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका या नगर पंचायतें शहरी अधोसंरचना के विकास की जिम्मेदारी उठाती हैं।

जनसंख्या वितरण और सामाजिक संरचना

जनगणना 2011 के अनुसार, बस्ती मंडल की कुल जनसंख्या 67,38,944 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 34,20,023 और महिलाओं की संख्या 33,18,921 है। जनसंख्या घनत्व 948 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के औसत घनत्व 829 व्यक्ति/वर्ग किमी से अधिक है। यह स्पष्ट करता है कि यह क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक सघन है (मोहम्मद *et al.*, 2021)।

मंडल की जनसंख्या का 93.65% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि केवल 6.35% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। यह आंकड़ा बस्ती मंडल की नगरीकरण स्थिति की एक बड़ी झलक प्रदान करता है — जहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया अभी भी प्रारंभिक स्तर पर है और अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर निर्भर है।

साक्षरता और शैक्षिक स्थिति

बस्ती मंडल की औसत साक्षरता दर 65.39% है, जो राष्ट्रीय औसत (2011 में 74.04%) से कम है। पुरुषों की साक्षरता दर 75.71% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 52.81% है। यह लिंग आधारित साक्षरता में भारी अंतर को दर्शाता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण, बुनियादी शैक्षिक संसाधनों की अनुपलब्धता, और सामाजिक रुढ़ियों का परिणाम माना जा सकता है (झाओ *et al.*, 2021)।

नगरीकरण की अल्पता का प्रत्यक्ष प्रभाव इस शैक्षिक असमानता में देखा जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या, संसाधनों की गुणवत्ता, शिक्षक-छात्र अनुपात और डिजिटल शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कमी दिखाई देती है। इससे ग्रामीण छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच कठिन हो जाती है, विशेषकर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए।

भाषाई और सांस्कृतिक विविधता

बस्ती मंडल भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की प्रमुख भाषाएँ हिंदी, भोजपुरी और अवधी हैं। ये भाषाएँ न केवल संपर्क का माध्यम हैं, बल्कि यहाँ के लोकगीत, साहित्य, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में गहराई से समाहित हैं। धार्मिक रूप से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और अन्य समुदाय निवास करते हैं, जो क्षेत्र की बहुसांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं।

वर्ष भर यहाँ कई सांस्कृतिक मेले, उत्सव और धार्मिक यात्राएँ आयोजित की जाती हैं, जैसे कि माघ मेला, रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा आदि। सिद्धार्थनगर जिले में स्थित कपिलवस्तु और पिपरहवा जैसे बौद्ध धार्मिक स्थल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं।

सीमा क्षेत्रीय विशिष्टता और नेपाल के साथ संबंध

बस्ती मंडल की एक और विशेषता इसकी नेपाल सीमा से सटी स्थिति है। यह स्थिति मंडल को अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सीमा क्षेत्र के कारण यहाँ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध दोनों देशों के नागरिकों के बीच गहरे हैं (झांग *et al.*, 2021)। साथ ही यह क्षेत्र व्यापार और आवागमन के दृष्टिकोण से भी सक्रिय रहता है।

नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की उपस्थिति और दोनों देशों की सहमति से चलने वाली आवागमन व्यवस्था कार्यरत है। इस संपर्क ने सीमावर्ती जनसंख्या के जीवन, संस्कृति और शिक्षा पर परोक्ष प्रभाव डाला है।

3. नगरीकरण की प्रक्रिया और वर्तमान स्वरूप

नगरीकरण एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है जो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन, तथा जीवनशैली में शहरी प्रभावों के समावेश को परिभाषित करती है। बस्ती मंडल में यह प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से धीमी किंतु सुसंगत रही है। यद्यपि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बस्ती मंडल आज भी एक अपेक्षाकृत ग्रामीण संरचना वाला मंडल है, तथापि पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में नगरीकरण की गति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है।

नगरीकरण के ऐतिहासिक संदर्भ और प्रारंभिक अवस्थाएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बस्ती मंडल की प्रशासनिक और आधारभूत संरचनाएँ मुख्यतः ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित थीं। पारंपरिक कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित परिवहन सुविधाओं के कारण यहाँ का शहरी विस्तार धीमा रहा। लेकिन जैसे-जैसे राज्य सरकार ने ग्रामीण संपर्क मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बिजली वितरण में निवेश बढ़ाया, वैसे-वैसे छोटे कस्बों और नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। इस क्रम में बस्ती नगर, खलीलाबाद, नौगढ़ और डुमरियागंज जैसे कस्बों ने स्थानीय व्यापार, शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और संचार माध्यमों की उपलब्धता के कारण धीरे-धीरे नगरीकरण के केंद्र के रूप में पहचान बनाई (बैटी *et al.*, 2021)।

आधुनिक नगरीकरण की रफ्तार और विस्तार की प्रवृत्तियाँ

वर्तमान समय में बस्ती मंडल का नगरीकरण बहुआयामी है। यह केवल जनसंख्या वृद्धि या ग्रामीण पलायन तक सीमित नहीं है, बल्कि

इसमें बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश प्रवृत्तियाँ, और शैक्षिक-सांस्कृतिक केंद्रों की वृद्धि जैसे अनेक आयाम जुड़े हुए हैं।

बस्ती नगर, मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय होने के कारण सबसे तीव्र नगरीकरण का अनुभव कर रहा है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासनिक कार्यालय और परिवहन सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। खलीलाबाद, जो कि संत कबीर नगर जिले का प्रमुख नगर है, एक उभरता हुआ औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बन चुका है, जहाँ छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए अवसर उत्पन्न हुए हैं। नौगढ़ और डुमरियागंज जैसे नगर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं और इनका विशेष महत्व नेपाल के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में है।

इन शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सुविधाओं की सुलभता के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है (डाडी *et al.*, 2021)।

शहरीकरण के डिजिटल विश्लेषण और डैशबोर्ड आधारित निगरानी प्रणाली

राज्य सरकार द्वारा विकसित डिजिटल पोर्टल्स जैसे SPIDER (Sankhikiya Patika), OSIS (Online Statistical Information System) और GIS आधारित राज्य सांख्यिकीय पोर्टल ने बस्ती मंडल में नगरीकरण की प्रवृत्तियों का आँकड़ों के माध्यम से मूल्यांकन करना संभव बनाया है।

SPIDER पोर्टल पर आधारित आँकड़े दर्शाते हैं कि बस्ती मंडल के नगरीकृत क्षेत्रों में विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, और अन्य शासकीय सेवाओं की सघनता अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अपेक्षाकृत कम है। यह अंतर नीति-निर्माताओं के लिए एक संकेत है कि संसाधनों के वितरण में असंतुलन बना हुआ है।

OSIS के माध्यम से विद्यालय-वार डेटा संकलन, शिक्षक उपस्थिति, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, एवं छात्र-छात्रा अनुपात जैसे संकेतकों का विश्लेषण संभव हुआ है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्रों में शैक्षिक व्यवस्थाओं की गुणवत्ता अधिक संगठित और सुव्यवस्थित है।

e-MANCHITRA, जो एक GIS आधारित मैपिंग पोर्टल है, बस्ती मंडल के भीतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना करते हुए यह स्पष्ट करता है कि जहाँ नगरीकृत क्षेत्रों में विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सेवाएँ एक निश्चित भौगोलिक दायरे में केंद्रित हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की पहुँच दूरवर्ती और असंतुलित है (फिट्रियंती *et al.*, 2021)।

नगरीकरण और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन

बस्ती मंडल में नगरीकरण ने केवल आर्थिक और भौतिक संरचनाओं को ही नहीं बदला है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन लाया है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब अधिक जागरूक, शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, बालिकाओं की विद्यालयों में उपस्थिति, कोचिंग और निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि जैसे तत्व नगरीकरण के प्रभाव में उभर कर सामने आए हैं।

इसके अतिरिक्त नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का कस्बों की ओर पलायन बढ़ा है। यह प्रवृत्ति एक ओर तो रोजगार और शिक्षा के नए अवसर उत्पन्न करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण संसाधनों पर असर डालती है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन में कमी, शिक्षकों की नियुक्ति में कठिनाई और स्थानीय शिक्षा प्रणाली पर बोझ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

नगरीकरण से जुड़ी समस्याएँ और अवसंरचनात्मक असंतुलन

बस्ती मंडल के शहरीकरण में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी समाहित हैं। जैसे-जैसे नगरीकृत क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आधारभूत सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ रहा है। शहरी विद्यालयों में कक्षाओं की भीड़, शिक्षक-छात्र अनुपात में असंतुलन, तथा शहरी झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा तक सीमित पहुँच – ये सभी समस्याएँ नगरीकरण के अनियंत्रित स्वरूप को दर्शाती हैं (वांग *et al.*, 2021)।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ नगरीकरण की पहुँच धीमी है, वहाँ सरकार द्वारा बनाए गए विद्यालयों और अन्य सेवाओं तक पहुँच एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में ICT आधारित शिक्षा, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षक प्रशिक्षण की योजनाएँ अभी तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी हैं।

सांख्यिकीय संकेत और विकास की संभावनाएँ

नगरीकरण से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यदि संसाधनों का समान वितरण और नीति आधारित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए तो बस्ती मंडल का नगरीकरण समावेशी बन सकता है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए RFP (Request for Proposal) for Survey Related Data Processing and Report Generation जैसे दस्तावेज यह प्रमाणित करते हैं कि शासन प्रशासन अब आँकड़ों पर आधारित योजनाओं को प्राथमिकता देने लगा है।

इन प्रयासों से यह संभव है कि बस्ती मंडल के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव पहुँच सकें — विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में (पुरोहित *et al.*, 2021)।

4. शैक्षिक सुविधाओं पर नगरीकरण का प्रभाव

नगरीकरण केवल आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को ही नहीं बदलता, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भारी असमानता व्याप्त है, वहाँ नगरीकरण ने शैक्षिक संसाधनों के वितरण और उपयोग की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। बस्ती मंडल जैसे क्षेत्रों में यह प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जहाँ शहरी इलाकों में शैक्षिक सुविधाओं का विकास तीव्र गति से हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को अब भी बुनियादी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है (अडेडेजी *et al.*, 2021)।

4.1 संस्थागत वितरण में असमानता

शैक्षिक संस्थानों के भौगोलिक वितरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक बड़ा अंतर देखा गया है। बस्ती मंडल के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई

है, और उनके बुनियादी ढांचे में भी गुणवत्ता देखी जा सकती है। इनमें पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट कक्षाएँ, खेलकूद की सुविधाएँ और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता शामिल है। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या तो ठीक-ठाक है, लेकिन उनमें आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी है। कई स्कूलों में पक्के भवन नहीं हैं, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, और पुस्तकालय या विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएँ नहीं हैं।

इस असमानता के कारण शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी शैक्षिक रूप से अधिक सशक्त बनकर उभरते हैं, जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह केवल शैक्षिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

4.2 डिजिटल असमानता और शैक्षिक पहुँच

डिजिटलीकरण और तकनीक की प्रगति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शहरी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएँ, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, और प्रशासनिक निगरानी हेतु ऑनलाइन सिस्टम जैसे OSIS (Online School Information System) और SPIDER जैसे पोर्टल्स का उपयोग आम हो गया है। ये पोर्टल शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी, स्कूल प्रबंधन और नीति निर्माण के लिए आवश्यक डेटा की उपलब्धता को आसान बनाते हैं (हुसैन *et al.*, 2021)।

परंतु, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ अभी भी इंटरनेट की अनियमित आपूर्ति, बिजली की समस्या और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। परिणामस्वरूप, डिजिटल शिक्षा का लाभ ग्रामीण विद्यार्थियों तक सीमित मात्रा में ही पहुँच पाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन हो गई, तब यह डिजिटल विभाजन और भी स्पष्ट हो गया। शहरी बच्चों ने जहाँ ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी रखी, वहीं ग्रामीण बच्चे डिजिटल संसाधनों के अभाव में पढ़ाई से कट गए।

4.3 शिक्षकों का स्थानिक असंतुलन

शिक्षक किसी भी शैक्षिक प्रणाली की रीढ़ होते हैं। नगरीकरण के कारण शिक्षकों का वितरण भी असंतुलित होता जा रहा है। शहरी विद्यालयों में न केवल शिक्षक संख्या अधिक है, बल्कि उनके प्रशिक्षण और दक्षता का स्तर भी अपेक्षाकृत उच्च है। वे नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और नई शिक्षण विधियों को अपनाते हैं।

इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूलों में केवल एक या दो शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें बहुविषयक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा, कई शिक्षक ग्रामीण नियुक्ति से बचने के लिए स्थानांतरण की मांग करते रहते हैं, जिससे इन विद्यालयों में स्थायित्व नहीं बन पाता। शिक्षक उपस्थिति की समस्या भी गंभीर है, जो ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक स्तर को प्रभावित करती है।

शिक्षकों की यह असमानता सीधे तौर पर शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। जब प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षक उपलब्ध नहीं होते, तब शिक्षा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। छात्रों में अधिगम रुचि कम हो जाती है, और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है (गुओ *et al.*, 2021)।

4.4 लिंगानुपात और शैक्षिक अवसर

नगरीकरण ने बालिका शिक्षा को भी प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण शहरी इलाकों में लड़कियों के लिए समर्पित विद्यालयों की उपलब्धता, छात्रावास सुविधाएं, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता है। इसके अलावा, शहरी परिवारों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत सकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है।

इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को लेकर अभी भी कई सामाजिक और भौतिक बाधाएं हैं। वहाँ बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की कमी, लंबी दूरी तय कर विद्यालय पहुँचने की मजबूरी, परिवहन की असुरक्षा, और माता-पिता की अशिक्षा प्रमुख समस्याएं हैं। इसके कारण किशोरावस्था में ही लड़कियों की शिक्षा छूट जाती है और उन्हें घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता है या कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है।

इस लिंग आधारित असमानता को दूर करने के लिए केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई जा रही "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसी योजनाएं तभी सफल होंगी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा (अहमद *et al.*, 2021)।

MANCHITRA, और GIS आधारित प्लेटफॉर्म प्रमुख हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षिक संसाधनों की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन एक वैज्ञानिक और स्थानिक दृष्टिकोण से किया जा सके। इस भाग में हम इन प्लेटफॉर्मों की कार्यप्रणाली, प्रभाव और नीति-निर्धारण में उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

5.1 e-MANCHITRA के माध्यम से स्थानिक विश्लेषण

e-MANCHITRA (मानचित्र आधारित स्कूल सूचना प्रणाली) एक अत्याधुनिक जीआईएस (GIS) तकनीक पर आधारित पोर्टल है, जिसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में स्थानिक असमानताओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए विकसित किया गया है (ज़ेंग *et al.*, 2021)। यह पोर्टल बस्ती मंडल के सभी जिलों और विकास खंडों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है।

इस पोर्टल के माध्यम से यह विश्लेषण संभव हुआ है कि कौन-से गांव या वार्ड ऐसे हैं जहाँ विद्यालय की पहुँच 1 किलोमीटर से अधिक है, अथवा प्राथमिक विद्यालय के बाद माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूरी 3 से 5 किलोमीटर से अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह पोर्टल छात्र-शिक्षक अनुपात, स्कूल में शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल के मैदान और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को भी भौगोलिक रूप से प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर, बस्ती मंडल के कई दूरस्थ इलाकों की पहचान की गई, जहाँ पर नए विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता थी। इस स्थानिक विश्लेषण की सहायता से न केवल स्कूल की भौगोलिक पहुँच बढ़ी है, बल्कि संसाधनों का न्यायसंगत वितरण भी सुनिश्चित हुआ है।

5.2 SPIDER के माध्यम से रिपोर्टिंग दक्षता

SPIDER (Statistical Portal for Integrated Data Evaluation and Reporting) उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा विकसित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग प्रणाली है, जो विद्यालयों से संबंधित नामांकन, परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, ड्रॉप-आउट दर, छात्रवृत्ति वितरण और अन्य प्रमुख मापदंडों पर रियल टाइम डेटा एकत्रित करता है।

बस्ती मंडल के सैकड़ों विद्यालय इस पोर्टल पर प्रतिदिन अपने अपडेट साझा करते हैं। इससे सरकार को यह जानने में मदद मिलती है कि किस विद्यालय में नामांकन दर घट रही है, कहाँ उपस्थिति नियमित नहीं है, और कौन-से क्षेत्र ड्रॉप-आउट हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं (शाओ *et al.*, 2021)।

इस डेटा के आधार पर, नीति-निर्माताओं को लक्षित हस्तक्षेप की योजना बनाने में सुविधा मिलती है। जैसे—यदि किसी क्षेत्र में बालिकाओं की उपस्थिति कम देखी गई, तो वहाँ पर सुरक्षित परिवहन व्यवस्था, बालिका छात्रावास और सेनेटरी सुविधाओं पर निवेश बढ़ाया गया।

5.3 OSIS और डैशबोर्ड आधारित निगरानी

OSIS (Online School Information System) के माध्यम से सभी विद्यालयों का एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें शैक्षिक संस्थानों के पंजीकरण से लेकर शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपलब्धि, अधोसंरचना और फंड उपयोग तक का विवरण डिजिटल रूप से संग्रहित होता है।

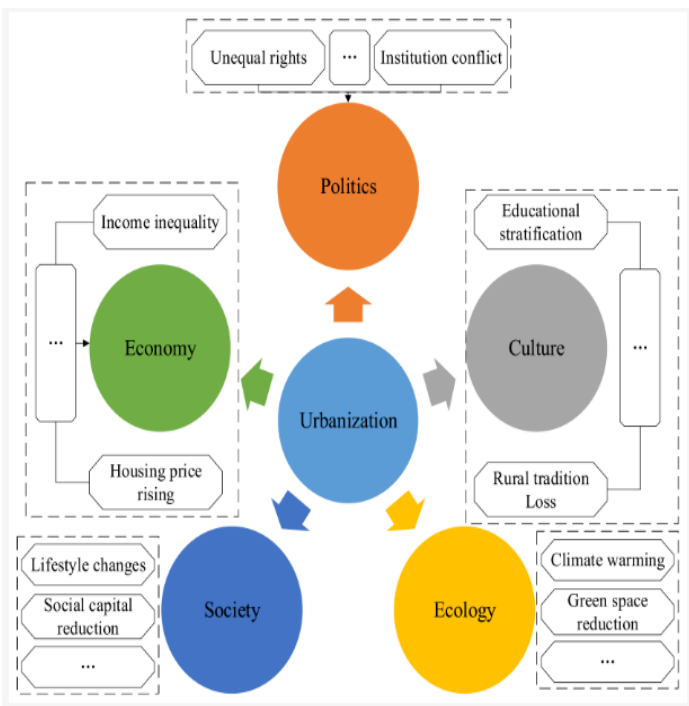


Figure: 1 बस्ती मंडल में नगरीकरण का शैक्षिक सुविधाओं पर प्रभाव

5. योजना, नीति और डेटा-संचालित प्रयास

शिक्षा के क्षेत्र में सटीक योजना और प्रभावी नीति निर्माण हेतु आज के युग में डेटा-संचालित निर्णय प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती मंडल सहित प्रदेश के अन्य मंडलों में शैक्षिक सुधार के लिए कई तकनीकी पहल की हैं, जिनमें SPIDER, OSIS, e-

बस्ती मंडल के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को OSIS डैशबोर्ड से प्रत्येक विद्यालय के प्रदर्शन की निगरानी करने की सुविधा मिली है। इससे न केवल निगरानी दक्षता बढ़ी है, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई विद्यालय नियमित रूप से डाटा रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाता है।

OSIS के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रशिक्षण जैसे कार्य भी सुव्यवस्थित हो गए हैं। साथ ही, विद्यालयों को आवंटित बजट का उपयोग, निर्माण कार्यों की प्रगति, और छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति भी इसी डैशबोर्ड से ट्रैक की जाती है (लिपी *et al.*, 2021)।

5.4 GIS आधारित योजना और पारदर्शिता

GIS तकनीक के माध्यम से अब यह संभव हुआ है कि शिक्षा विभाग को सटीक भौगोलिक जानकारी प्राप्त हो—जैसे किस गांव या बस्ती में स्कूल नहीं है, या फिर कहाँ छात्र-शिक्षक अनुपात अत्यधिक विकृत है। इस तकनीक ने पारंपरिक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को वैज्ञानिक और तथ्याधारित बना दिया है।

बस्ती मंडल में GIS आधारित डाटा का उपयोग कर प्राथमिक स्तर पर लगभग 150 नए विद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की गई, जिनमें से अधिकांश सुदूर और पिछड़े इलाकों में हैं। इसी प्रकार, शिक्षकों की कमी वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर वहाँ तत्काल तैनाती की गई।

5.5 नीति-निर्माण में डेटा की भूमिका

आज की शिक्षा नीतियाँ बिना सटीक और अद्यतन डेटा के कारगर नहीं हो सकतीं। बस्ती मंडल में इन तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार को ऐसी नीति बनाने में सहायता मिली है, जो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सक्षम है। अब नीतियाँ केवल राज्य या मंडल स्तर पर नहीं, बल्कि ज़िले, ब्लॉक और गाँव स्तर पर भी तैयार हो रही हैं (म्वीन्डे *et al.*, 2021)।

इन प्रयासों के कारण सरकारी बजट का उपयोग भी अधिक प्रभावशाली ढंग से हो रहा है। पहले जहाँ योजनाएँ केवल अनुमानों पर

आधारित होती थीं, वहीं अब स्थान-विशेष आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनती हैं। इससे संसाधनों की बर्बादी भी कम हुई है।

6. नगरीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ

6.1 ग्रामीण पलायन और विद्यालयों पर भार

नगरीकरण के कारण ग्रामीण छात्र अधिक सुविधा की तलाश में कस्बों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे एक ओर तो ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन घट रहा है, वहीं दूसरी ओर शहरी विद्यालयों में भार बढ़ रहा है।

6.2 सामाजिक असमानता की वृद्धि

शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण इन क्षेत्रों से निकलने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार में आगे रहते हैं, जबकि ग्रामीण छात्र अवसरों से वंचित हो जाते हैं, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती है (पैन *et al.*, 2021)।

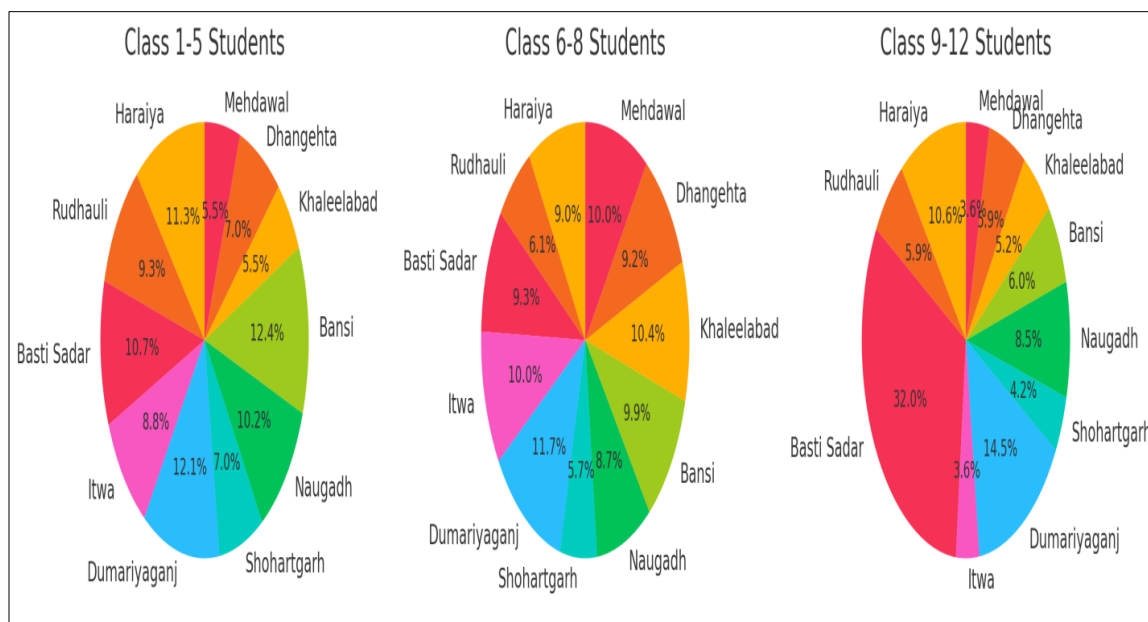
7. समाधान एवं सिफारिशें

बस्ती मंडल में शैक्षिक असमानताओं को कम करने एवं नगरीकरण से उत्पन्न प्रभावों का संतुलन स्थापित करने हेतु निम्न प्रयास आवश्यक हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल आधारभूत संरचना को मज़बूत कर SPIDER और OSIS जैसे पोर्टलों की पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाया जाए।
- महिला शिक्षा के लिए अलग विद्यालय, छात्रावास, और सेफ ट्रांसपोर्ट जैसे उपाय बढ़ाए जाएँ।
- शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता बरती जाए।
- GIS आधारित e-MANCHITRA प्लेटफॉर्म से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शिक्षा संबंधी बजट और संसाधनों का स्थानिक आवंटन किया जाए।

नगरीकरण के शैक्षिक डेटा को तालिका

तहसील	कक्षा 1-5 तक छात्रों की संख्या	कक्षा 6-8 तक छात्रों की संख्या	कक्षा 9-12 तक छात्रों की संख्या	कुल छात्र	कक्षा 1-5 तक शिक्षक	कक्षा 6-8 तक शिक्षक	कक्षा 9-12 तक शिक्षक
हरैया	16,232	6,385	4,504	27,121	2,736	1,085	708
रूधौली	13,420	4,280	2,495	20,195	2,015	635	430
बस्ती सदर	15,422	6,535	13,559	35,516	3,284	2,880	2,911
इटवा	12,708	7,054	1,537	21,299	2,352	2,286	192
डुमरियागंज	17,409	8,285	6,149	31,843	3,881	1,482	151
शोहरतगढ़	10,124	4,042	1,785	15,951	4,021	817	228
नौगढ़	14,704	6,168	3,625	24,497	1,696	1,312	273
बांसी	17,875	7,002	2,545	27,422	4,016	876	121
खलीलाबाद	7,841	7,316	2,195	17,352	2,173	2,157	299
धनघटा	10,124	6,463	2,495	19,082	3,391	1,482	151
मेहदावल	7,944	7,054	1,537	16,535	2,352	2,286	121



3. नगरीकरण और शैक्षिक सुविधाओं का आपसी संबंध

नगरीकरण का सीधा संबंध जनसंख्या घनत्व, संसाधनों की उपलब्धता और सेवाओं की पहुँच से है।

- **बस्ती तहसील** में सर्वाधिक घनत्व (1,146 व्यक्ति/किमी²) और बेहतर संपर्क व्यवस्था होने से उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, डिजिटल कक्षाएँ और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता अधिक है।
- **हरैया** का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लेकिन घनत्व (783 व्यक्ति/किमी²) कम होने से कई गाँव शैक्षिक केंद्रों से दूर हैं।
- **भानपुर** और **रुधौली** अपेक्षाकृत कम शहरीकृत हैं, जहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों और डिजिटल सुविधाओं की कमी है।

4. साक्षरता और लैंगिक असमानताएँ

साक्षरता दर में अंतर नगरीकरण की असमानता को दर्शाता है:

- **बस्ती तहसील** शहरी केंद्रों के कारण अपेक्षाकृत बेहतर साक्षरता दर रखता है, फिर भी यह राज्य और राष्ट्रीय औसत से कम है।
- **रुधौली तहसील** की साक्षरता दर सबसे कम (54.1%) है, हालांकि यहाँ लिंगानुपात (~1001) संतुलित है, जो सामाजिक दृष्टि से महिलाओं के प्रति सकारात्मक रुझान दर्शाता है, लेकिन पर्याप्त शैक्षिक ढाँचे की कमी बनी हुई है।
- ग्रामीण तहसीलों में लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि परिवहन, अलग विद्यालय और सुरक्षित माहौल की कमी है।

5 संस्थागत और डिजिटल अवसंरचना का वितरण

सरकारी पोर्टल (SPIDER, OSIS, e-MANCHITRA) के आंकड़ों से पता चलता है:

- **बस्ती तहसील**: विज्ञान प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएँ और इंटरनेट सुविधा वाले संस्थानों का उच्च संकेंद्रण।

- **हरैया**: मध्यम स्तर का अवसंरचना विकास, लेकिन तहसील के भीतर असमान वितरण — शहरी केंद्रों के पास के क्षेत्र अधिक विकसित।
- **भानपुर और रुधौली**: डिजिटल शिक्षा का सीमित उपयोग; कई स्कूलों में कंप्यूटर लैब और स्थायी बिजली की कमी।

6 शिक्षक वितरण और संसाधन आवंटन

शिक्षकों का वितरण असंतुलित है:

- बस्ती तहसील शहरी सुविधाओं के कारण योग्य शिक्षकों को अधिक आकर्षित करता है।
- रुधौली और भानपुर में शिक्षक बने रहने में कठिनाई, जिसके चलते बहुविषयक कक्षाएँ और ड्रॉपआउट दर में वृद्धि।
- GIS विश्लेषण से पता चलता है कि हरैया और भानपुर के कई क्षेत्रों में छात्र-शिक्षक अनुपात 50:1 से अधिक है।

7 नीतिगत और योजना संबंधी निष्कर्ष

तहसीलवार आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि:

1. **लक्षित हस्तक्षेप**: रुधौली और भानपुर में डिजिटल अवसंरचना और बालिका शिक्षा सुविधाओं में निवेश आवश्यक।
2. **संपर्क सुधार**: हरैया में ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी बढ़ाकर शैक्षिक पहुँच बेहतर की जा सकती है।
3. **शिक्षक प्रोत्साहन**: कम घनत्व वाले और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों को अतिरिक्त सुविधाएँ देकर उनकी नियुक्ति को बढ़ावा।
4. **GIS आधारित योजना**: e-MANCHITRA और OSIS डेटा के आधार पर सूक्ष्म स्तर पर संसाधन आवंटन।

निष्कर्ष

बस्ती मंडल में नगरीकरण एक ओर शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर यह ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक असमानता को भी जन्म दे रहा है। शासन की डिजिटल पहलें जैसे SPIDER, OSIS, और

e-MANCHITRA यदि सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जाएँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी और संतुलित विकास संभव है। इस दिशा में शासकीय नीतियाँ, स्थानीय भागीदारी और डिजिटल समावेशन ही बस्ती मंडल के शैक्षिक परिदृश्य को भविष्य में सशक्त बना सकते हैं।

संदर्भ

1. Abubakar A, Bala A, David SS, Abdullahi H, Kodan YM. सुलेजा, नाइजर राज्य, नाइजीरिया में शैक्षिक भूमि उपयोग पर नगरीकरण का प्रभाव. *जर्नल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट*. 2022;4(1):45-51.
2. Adamu B, Shidali SD, Habib A, Yisa MK. सुलेजा, नाइजर राज्य, नाइजीरिया में शैक्षिक भूमि उपयोग पर नगरीकरण का प्रभाव. 2021.
3. Humble A, Choudhary N, Pathak B. नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता. In: *क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी*. सिंगापुर: स्प्रिंगर नेचर; 2023. पृ.151-66.
4. Mohammed AM, Yukai T. विश्वविद्यालय परिसरों का नगरीकरण पर प्रभाव: जापान के क्यूशू विश्वविद्यालय परिसरों का एक सामाजिक और स्थानिक विश्लेषण. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग*. 2021;16(7):1209-20.
5. Zhao X, Liu L. चीन में शहरी-ग्रामीण आय अंतर पर नगरीकरण स्तर का प्रभाव: एक स्थानिक अर्थमितीय मॉडल पर आधारित अध्ययन. *सस्टेनेबिलिटी*. 2022;14(21):13795.
6. Zhang C, Zhou W. सतत नगरीकरण की नई दिशा: चीन में डिजिटल तकनीकों और नीतियों का स्थानिक नगरीकरण पर प्रभाव. *बिल्डिंग्स*. 2022;12(7):882.
7. Benti S, Terefe H, Cailo-Concha D. इथियोपिया के नगरीकरण में उपेक्षित कारकों की भूमिका: भविष्य के उभरते शहरों में अनियोजित विकास की समस्या की रोकथाम. *हेलीऑन*. 2022;8(10).
8. Dadi W, Mulugeta M, Semi N. खेतिहर परिवारों के कल्याण पर नगरीकरण का प्रभाव: इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्रीय राज्य के अदामा ग्रामीण जिले से साक्ष्य. *हेलीऑन*. 2024;10(1).
9. Fitriyanti AN, Achsanuddin AN, Adelia S. मकास्सर शहर में नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक. *प्वाइंट ऑफ व्यू रिसर्च इकोनॉमिक डेवलपमेंट*. 2021;2(1):32-41.
10. Wang Q, Zhang F, Li R. नगरीकरण के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत विकास: एआई अनुसंधान, आधारभूत संरचना और बाजार लाभ का दृष्टिकोण. *सस्टेनेबल डेवलपमेंट*. 2025;33(1):1136-56.
11. Purohit S. भारत के द्वितीय श्रेणी शहरों से उदाहरण: क्षेत्रीय सतत विकास में औद्योगीकरण और नगरीकरण की भूमिका. 2023.
12. Adedeji I. नाइजीरिया में नगरीकरण और किफायती आवास का महत्व. *जर्नल ऑफ सर्विस साइंस एंड मैनेजमेंट*. 2023;16(3):351-68.
13. Hossain MB, Khan JR, Adhikari AC, Anwar AM, Rahim E, Siddiqui MH, Hossain MS. विकासशील देशों में बाल मोटापा और नगरीकरण के बीच संबंध: बांग्लादेश से साक्ष्य. *जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ*. 2022;30(12):2819-28.
14. Guo A, Ullah O, Zeb A, Din NU, Hussain S. SAARC देशों (1990-2022) में CO₂ उत्सर्जन, नगरीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा का जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर पर प्रभाव. *नेचुरल रिसोर्सेस फोरम*. 2025;49(2):1795-822.
15. Ahmad N, Raid M, Alzyadat J, Alhawal H. दक्षिण एशियाई देशों में नगरीकरण और आय विषमता का जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव: स्वास्थ्य खर्च की मध्यस्थ भूमिका. *ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस*. 2023;10(1):1-9.
16. Zeng C, Deng X, Yang J, Cheng Y, Zhao T, Wang P. चीन में समुदाय स्तर पर पारिस्थितिक नगरीकरण की धारणा और प्रेरक कारकों की खोज. *सिटीज*. 2022;122:103513.
17. Shao Q, Tao R, Luka MM. चीन में स्वास्थ्य व्यय पर नगरीकरण का प्रभाव. *फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ*. 2022;10:850872.
18. Lipi Al, Hasan N. बांग्लादेश में नगरीकरण: उभरती चुनौतियाँ और आगे की दिशा. *बांग्लादेश जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिफिक रिसर्च*. 2021;3(1):33-44.
19. Ridwan M. बांग्लादेश में वैश्वीकरण, नगरीकरण और आर्थिक विकास के बीच संबंध: एक नवीन ARDL दृष्टिकोण. 2023.
20. Mwiinde C, Munshifwa EK. जाम्बिया के शहरों में नगरीकरण, गरीबी और बेघरपन: सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक खतरा. In: *होमलेसनेस टू होप*. एल्सेवियर; 2024. पृ.37-51.
21. Teye DA, Ocansey RT. घाना में स्वास्थ्य और भलाई पर नगरीकरण का प्रभाव: अनुसंधान की स्थिति, हस्तक्षेप रणनीतियाँ और भविष्य की दिशा. *फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ*. 2022;10:877920.
22. Pan M, Huang Y, Qin Y, Li X, Lang W. जिला नगरीकरण की पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा संसाधनों के आवंटन की समस्याएँ और रणनीतियाँ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ*. 2022;19(21):14596.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Corresponding Author



Ganesh Tripathi, भूगोल विभाग, बुद्धा पी.जी. कॉलेज, कुशीनगर में शोधार्थी हैं, जो डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इनका शोध क्षेत्र शहरीकरण, क्षेत्रीय विकास और शैक्षिक सुविधाओं पर इसके प्रभाव से संबंधित है। इन्होंने विभिन्न सेमिनार और शोधपत्रों में सक्रिय भागीदारी की है।